

GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र

Delhi Gazette



प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 14 | दिल्ली, नवम्बर 20—नवम्बर 26, 2015, बुधस्तिवार/कार्तिक 29—अग्रहायण 5, 1937 [रा.रा.क्षे. दि. सं. 147]
 No. 14 | DELHI, NOVEMBER 20—NOVEMBER 26, 2015, THURSDAY/KARTIKA 29—AGRAHAYANA 5, 1937 [N.C.T.D. No. 147]

भाग II—I

PART II—I

न्यायिक और मजिस्ट्रेरी मामलों पर अधिसूचनाएं और आदेश, उच्च न्यायालय की अधिसूचनाएं और भारत के निर्वाचन आयोग की विधिक अधिसूचनाओं तथा अन्य निर्वाचन अधिसूचनाओं का पुनः प्रकाशन

Notifications and Orders on Judicial and Magisterial matters, reproduction of High Court Notifications and Statutory Notifications of the Election Commission of India and other Election Notifications

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली

अधिसूचनाएं

दिल्ली, 23 सितम्बर, 2015

सं. 541/स्था./ई-2/डी. एच. सी.—माननीय मुख्य न्यायाधीश इस न्यायालय की स्थापना में निम्नलिखित नियुक्ति सहर्ष करती हैं :

क्र. सं.	अधिकारी का नाम एवं धारित पद	पद जिस पर नियुक्ति की गई है	टिप्पणियाँ
1.	श्री ग्रागेश मोहन, वरिष्ठ न्यायिक सहायक	रु. 15600-39100 के वेतन बैंड में रु. 6600 के ग्रेड वेतन सहित अस्थायी कोर्ट मास्टर ।	दिनांक 22-09-2015 से आगामी आदेशों तक, 25% वरिष्ठता कोटा के अंतर्गत कोर्ट मास्टर के रिक्त पद के प्रति जो सुश्री अनीता जोशी, कोर्ट मास्टर की सेवानिवृत्ति पर उपलब्ध हुआ है ।

नोट: 1. उपरोक्त अधिकारी दिनांक 30-4-2016 तक, 60 वर्ष की आयु प्राप्ति पर उनकी अधिवर्षिता की आयु तक, परीक्षा पर रहेंगे।

2. उपरोक्त नियुक्ति वरिष्ठ न्यायिक सहायक के 8 पदों को कल्पित आधार पर भरने हेतु होने वाली विशेष पुनरवलोकन विभागीय परीक्षा, के परिणाम के भी अध्यधीन होगी जिसमें इस न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 4077-84/2004 शीर्षक "अतुल कुमार शर्मा एवं अन्य बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय" के दिनांक 23-10-2009 एवं 01-06-2012 के निर्देशों तथा माननीय मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिनांक 24-03-2015 को विधिवत अनुमोदित कार्यान्वयन समिति की रिपोर्ट द्वारा दिनांक 19-03-2015 को गई सिफारिश के अनुसार तथा रिट याचिका (सिविल) सं. 5884/15 शीर्षक "रविंदर पाहुजा व अन्य बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय व

अन्य" व रिट याचिका (सिविल) सं. 4077-84/2004 शीर्षक "अतुल कुमार शर्मा व अन्य बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय" में सिविल विविध सं. 8204/12 व 12236/15 के अनुसार केवल वे अधिकारी जो वर्ष 1988-2000 की अवधि के दौरान योग्य थे ही अनुमत किये जाने हैं। तथा आगे इस शर्त के अधधीन होगी कि उपरोक्त निर्णयों के क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप यदि उनका वरिष्ठता स्तर अवनत होता है तो वे अपना स्थान अपने से ऊपर आसीन अधिकारी (गण) कर्मचारी (गण) हेतु छोड़ने के लिए बाध्य होंगे एवं यदि कोई रिक्ति उपलब्ध नहीं होती है तो वे प्रत्यावर्तित हो जायेंगे।

3. सुश्री सुनीला शिबु की प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक) के अस्थायी पद पर नियुक्ति में अधिसूचना संख्या 424/स्थापना/ई-2/डी.एच.सी. दिनांक 01-07-2015 के नोट सं. 1 द्वारा लगाई गयी शर्त हटाई जाती है।

HIGH COURT OF DELHI : NEW DELHI

NOTIFICATIONS

Delhi, the 23rd September, 2015

No. 541/Estt/E-2/DHC.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to make the following appointments on the Establishment of this Court :—

S. No.	Name of the Official & Post held	Post to which appointed	Remarks
1	Mr. Yugesh Mohan, Senior Judicial Assistant	Temporary Court Master in the Pay Band of Rs.15600-39100 with Grade Pay of Rs. 6600	With effect from 22.09.2015 till further orders, against the vacant post of Court Master under 25% seniority quota which has become available on retirement of Ms. Anita Joshi, Court Master.

NOTE : 1. The above mentioned officer will be on probation till 30.04.2016, the date of his superannuation on attaining the age of 60 years.

2. The above appointment shall further be subject to outcome of the special review departmental test to be held for filling up 8 posts of Senior Judicial Assistant on notional basis in which the officials who were eligible during the period 1988-2000 alone are to be permitted as per directions dated 23.10.2009 and 1.6.2012 of this Court in W.P.(C) No. 4077-84/2004 titled 'Atul Kumar Sharma & Ors vs. High Court of Delhi', and as recommended by the Implementation Committee vide report dated 19.03.2015 duly approved by Hon'ble the Chief Justice on 24.03.2015, and W.P.(C) No. 5884/2015 titled "Ravinder Pahuja and Others vs. High Court of Delhi & Ors.", C.Ms. No. 8204/2012 and 12236/2015 in W.P (C) No. 4077-84/2004 titled "Atul Kumar Sharma & Ors. vs High Court of Delhi", as also subject to the condition that in case as a result of implementation of above decisions his seniority position is depressed, he will be liable to yield his position to the officer(s)/official(s) placed senior to him and in case no vacancy is available, he shall stand reverted.

3. The condition imposed on the appointment of Ms.Sunila Shibu to the temporary post of Admn. Officer (Judl.) vide Note No.1 of Notification No. 424/Estt./E2/DHC dated 01.07.2015 stands lifted/withdrawn.

दिल्ली, 1 अक्टूबर, 2015

सं. 543/स्था./ई-2/डी. एच. सी.— माननीय मुख्य न्यायाधीश इस न्यायालय की स्थापना में निम्नलिखित नियुक्तियाँ सहर्ष करती हैं :

क्र. सं.	अधिकारी का नाम एवं धारित पद	पद जिस पर नियुक्ति की गई है	टिप्पणियाँ
1.	श्री दीप चंद, वरिष्ठ न्यायिक सहायक	रु. 15600-39100 के वेतन बैंड में रु. 6600 के ग्रेड वेतन सहित अस्थाई कोर्ट मास्टर ।	दिनांक 01-10-2015 से आगामी आदेशों तक, 25% वरिष्ठता कोटा के अंतर्गत कोर्ट मास्टर के रिक्त पद के प्रति जो श्री आर. के. शर्मा, कोर्ट मास्टर की सेवानिवृत्ति होने पर उपलब्ध हुआ है ।

नोट: 1. उपरोक्त अधिकारी की नियुक्ति प्रारम्भिक रूप से उनकी नियुक्ति की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए परीक्षा पर होगी और परीक्षा अवधि की समाप्ति उनके स्वतः स्थायीकरण में परिणत नहीं होगी ।

2. उपरोक्त नियुक्ति वरिष्ठ न्यायिक सहायक के आठ पदों को कल्पित आधार पर भरने हेतु होने वाली विशेष पुनरावलोकन विभागीय परीक्षा, के परिणाम के भी अध्यधीन होगी जिसमें इस न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 4077-84/2004 शीर्षक "अतुल कुमार शर्मा व अन्य बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय" के दिनांक 23-10-2009 और 01-06-2012 के निर्देशों तथा माननीय मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिनांक 24-03-2015 को विधिवत अनुमोदित क्रियान्वयन समिति की रिपोर्ट द्वारा दिनांक 19-03-2015 को की गई सिफारिश के अनुसार तथा रिट याचिका (सिविल) सं. 5884/15 शीर्षक "रविंदर पाहुजा व अन्य बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय व अन्य" एवं रिट याचिका (सिविल) सं. 4077-84/2004 शीर्षक "अतुल कुमार शर्मा व अन्य बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय" में सिविल विविध सं. 8204/12 व 12236/15 के अनुसार केवल वे अधिकारी जो वर्ष 1988-2000 की अवधि के दौरान योग्य थे ही अनुमत किये जाने हैं। तथा आगे इस शर्त के अध्यधीन होगी कि उपरोक्त निर्णयों के क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप यदि उनका वरिष्ठता स्तर अवनत होता है तो वे अपना स्थान अपने से ऊपर आसीन अधिकारी (गण) कर्मचारी (गण) हेतु छोड़ने के लिए बाध्य होंगे एवं यदि कोई रिक्त उपलब्ध नहीं होती तो वे प्रत्यावर्तित हो जायेंगे ।

विनोद गोयल, महानिबंधक

Delhi, the 1st October, 2015

No. 543/Estt/E-2/DHC.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to make the following appointments on the Establishment of this Court :—

S. No.	Name of the Official & Post held	Post to which appointed	Remarks
1.	Mr. Deep Chand, Senior Judicial Assistant	Temporary Court Master in the Pay Band of Rs.15600-39100 with Grade Pay of Rs.6600	With effect from 01.10.2015 till further orders, against the vacant post of Court Master under 25% seniority quota which has become available on retirement of Mr. R. K. Sharma, Court Master.

NOTE : 1. Appointment of above mentioned officer will be on probation initially for a period of one year from the date of his appointment and expiry of the period of probation shall not result in his automatic confirmation.

2. The above appointment shall further be subject to outcome of the special review departmental test to be held for filling up 8 posts of Senior Judicial Assistant on notional basis in which the officials who were eligible during the period 1988-2000 alone are to be permitted as per directions dated 23.10.2009 and 1.6.2012 of this Court in W.P.(C) No. 4077 -84/2004 titled 'Atul Kumar Sharma & Ors vs. High Court of Delhi', and as recommended by the Implementation Committee vide report dated 19.03.2015 duly approved by Hon'ble the

Chief Justice on 24.03.2015, and W.P.(C) No. 5884/2015 titled "Ravinder Pahuja and Others vs. High Court of Delhi & Ors.", C.Ms. No. 8204/2012 and 12236/2015 in W.P (C) No. 4077-84/2004 titled "Atul Kumar Sharma & Ors. vs. High Court of Delhi", as also subject to the condition that in case as a result of implementation of above decisions his seniority position is depressed, he will be liable to yield his position to the officer(s)/ official(s) placed senior to him and in case no vacancy is available, he shall stand reverted.

VINOD GOEL, Registrar General